नईदुनिया

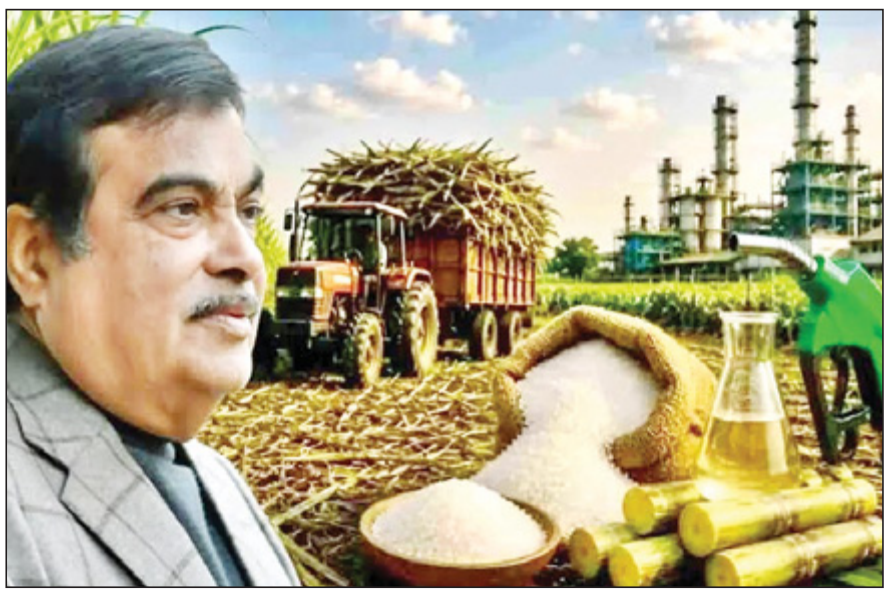

सिर्फ चीनी नहीं, अब ईंधन से होगी चीनी मिलों की बंपर कमाई

नई दिल्ली

देश में बढ़ती चीनी की कीमतें जहां आम आदमी के बजट पर भारी पड़ रही हैं, वहीं चीनी मिलों के लिए भी केवल चीनी बेचकर मुनाफा कमाना आसान नहीं रहा है। इसी समस्या का समाधान सुझाते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चीनी मिलों को एक नई दिशा दिखाई है।

उन्होंने मिलों से अपील की है कि वे सिर्फ चीनी उत्पादन तक सीमित न रहें, बल्कि गन्ने और उसके कचरे का इस्तेमाल कर इथेनाल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) जैसे अन्य उत्पाद बनाकर अपनी आय बढ़ाएं। यह कदम न केवल मिलों को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चीनी मिलों को सलाह दी है कि वे अब केवल चीनी के उत्पादन और बिक्री पर ही ध्यान केंद्रित न करें।

बढ़ती चीनी कीमतों के बीच केंद्रीय मंत्री गडकरी ने मिलों को दिया आत्मनिर्भरता का मंत्र

उनका मानना है कि मिलों को अब गन्ने और उससे निकलने वाले कृषि अपशिष्टों का सदुपयोग करते हुए अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्माण पर जोर देना चाहिए। गडकरी के अनुसार, इथेनाल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, बायो-फर्टिलाइजर और कंप्रेस्ड बायो जैसे उत्पाद चीनी मिलों की कमाई में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं। इस दिशा में इथेनाल उत्पादन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मध्य-पूर्व में तनाव के चलते पेट्रोल-डीजल आपूर्ति पर पड़े असर ने सरकार को इथेनाल ब्लेंडिंग (ई20 पेट्रोल) को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया है, जिससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम की जा सके। देश में इथेनाल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए चीनी मिलों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसी तरह गन्ने की खोई और अन्य जैविक कचरे से सीबीजी का निर्माण, देश की गैस, पेट्रोल और डीजल के लिए विदेशी निर्भरता को काफी हद तक घटा सकता है।

गडकरी ने स्पष्ट किया कि कृषि और दूसरे जैविक कचरे से सीबीजी बनाने से जीवाश्म ईंधन के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने में काफी मदद मिल सकती है। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि चीनी मिलों द्वारा इन वैकल्पिक ईंधनों और उत्पादों का उत्पादन न केवल उनकी आय में भारी वृद्धि करेगा, बल्कि इससे गन्ना किसानों को भी उनकी उपज का बेहतर और अधिक दाम मिल पाएगा। यह पहल चीनी उद्योग को केवल चीनी उत्पादक से ऊर्जा उत्पादक तक बदलने की क्षमता रखती है, जिससे देश की आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

न्यूज ब्रीफ

सरकार ने तंबाकू मुक्त निकोटीन पाउच पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध, बिक्री, विज्ञापन और वितरण पर पूर्ण रोक

नई दिल्ली। भारत सरकार ने युवाओं में तेजी से लोकप्रिय हो रहे तंबाकू मुक्त निकोटीन पाउच की बिक्री, विज्ञापन और वितरण पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इन उत्पादों को जब्त करने का भी आदेश दिया गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इन सिंथेटिक निकोटीन पाउच को युवाओं के लिए अत्यधिक नशीला और दिल व दिमाग के लिए बेहद खतरनाक बताया है, जिसके बाद सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ई-सिगरेट प्रतिबंध कानून (पीईसीए 2019) और खाद्य सुरक्षा मानकों (एफएसएसएआई) के तहत इनके आनलाइन व आफलाइन बाजारों पर तुरंत छापेमारी के निर्देश दिए हैं! सरकार का लक्ष्य पान की दुकानों, ई-कामर्स साइटों और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को लक्षित कर फैल रहे इस नए तरह के नशे के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाना है! ये पाउच, जिनमें निकोटीन होता है पर तंबाकू नहीं, भारत में बेचने के लिए अधिकृत नहीं हैं और पूरी तरह अवैध हैं! बावजूद इसके, जिन और व्हाइट फाक्स जैसे विदेशी ब्रांड्स की तस्करी कर 18 से 40 साल के युवाओं के बीच इन्हें बेचा जा रहा है। बड़ी तंबाकू कंपनियां सिगरेट के विकल्प के तौर पर इन्हें बढ़ावा दे रही थीं, क्योंकि इन पर अभी कड़े नियम लागू नहीं थे। देश में हर साल तंबाकू से 13.5 लाख लोगों की मौत होती है।

बैंक हड़ताल के तीन दिन एटीएम से फ्री ट्रांजेक्शन, 28 से 30 सितंबर तक एटीएम ट्रांजेक्शन पर लगने वाला अतिरिक्त शुल्क माफ

नई दिल्ली। देशभर में 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिवसीय बैंक हड़ताल से पहले ग्राहकों के लिए एक अहम राहत की खबर सामने आई है। सरकारी बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से नकदी निकालने पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क को माफ करने का फैसला किया है। अब इन तीन दिनों में ग्राहक मुफ्त एटीएम ट्रांजेक्शन की निर्धारित सीमा से अधिक बार भी बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के नकदी निकाल सकेंगे, जिससे हड़ताल के कारण होने वाली असुविधा कुछ कम होगी। सरकारी बैंकों का राहत भरा ऐलान स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), बैंक आफ बड़ौदा (बीओबी), यूनियन बैंक आफ इंडिया और इंडियन बैंक जैसे प्रमुख सरकारी बैंकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस फैसले की घोषणा की है। उन्होंने अपने आधिकारिक पेजों पर पोस्ट कर ग्राहकों को सूचित किया है। इसका सीधा मतलब है कि ग्राहक अपनी बैंक के एटीएम के अलावा किसी अन्य बैंक के एटीएम से भी तय मुफ्त सीमा से अधिक बार नकदी निकालने पर अब अतिरिक्त शुल्क नहीं देंगे, जो सामान्य परिस्थितियों में वसूला जाता है।

टाटा मोटर्स की नई सेडान एरिस लान्च, नए फीचर्स से है लैस

नई दिल्ली। कार निर्माता स्वदेशी कंपनी टाटा मोटर्स अपनी नई सेडान एरिस को लान्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने इसके इंटीरियर का एक नया वीडियो टीजर जारी किया है, जो ग्राहकों को अपनी ओर खींच सकते हैं। वीडियो में इंटीग्रेटेड डैशकैम फीचर वाला 360-डिग्री कैमरा भी नजर आ रहा है। एरिस का डैशबोर्ड लेआउट काफी हद तक नई जनरेशन टियागो जैसा दिखता है, हालांकि पूरे केबिन में बैज कलर थीम का इस्तेमाल किया गया है। एरिस के डैशबोर्ड पर दो सेंट्रल एसी वेंट्स के ऊपर एक फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन और उसके नीचे फिजिकल स्विच की लाइन दी गई है। इसमें ग्लास-ब्लैक क्लाइमेट-कंट्रोल पैनल में दो रोटरी नाब और एरिस लिखा हुआ है। सीटों और एडजस्टेबल फ्रंट हेडरेस्ट पर भी बैज कलर का उपयोग किया गया है। टीजर में टू-स्पोक मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील और पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिखाया गया है। सेंटर कंसोल पर एक रोटरी सेलेक्टर दिख रहा है, जिससे यह एएमटी वर्जन होने का संकेत मिलता है, और इसमें पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। यह एरिस का सीएनजी एएमटी वर्जन भी हो सकता है।

आईआरडीएआई के कमीशन कटौती प्रस्ताव से बदलेगी बैंकों की बीमा रणनीति

टर्म, हेल्थ व मोटर बीमा पर सीधा असर, बैंक उत्पादों के मिश्रण व वितरण माडल में करेंगे बदलाव

नई दिल्ली

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने बीमा वितरण कमीशन में बड़ी कटौती का प्रस्ताव दिया है, जिससे बैंकएश्योरेंस माडल पर सीधा असर पड़ेगा। इस कदम से बीमा उत्पादों के प्रमुख वितरक बैंकों को अपनी मौजूदा रणनीति और कमाई के तरीकों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह बदलाव बैंकों के उत्पाद मिश्रण, वितरण माडल और आय संरचना को प्रभावित करेगा, विशेषकर छोटे बैंकों के लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं। बैंकों की कमाई पर दिखेगा असर: आईआरडीएआई के प्रस्ताव के तहत विभिन्न बीमा उत्पादों और वितरण चैनलों के लिए कमीशन की नई सीमाएं तय की गई हैं। टर्म इंश्योरेंस में कमीशन मौजूदा 51 फीसदी से घटकर व्यक्तिगत एजेंटों के लिए अधिकतम 30 फीसदी और कारपोरेट वितरकों के लिए 25 फीसदी हो सकता है।

इसी तरह, स्वास्थ्य बीमा में यह 24 फीसदी से घटकर व्यक्तिगत वितरकों के लिए 20 फीसदी और कारपोरेट वितरकों के लिए 15 फीसदी प्रस्तावित है। वाहन बीमा में कमीशन को मौजूदा 26 फीसदी से घटाकर 0-15 फीसदी के दायरे में लाने का प्रस्ताव है, वहीं बचत वाले बीमा उत्पादों में भी कमीशन की मौजूदा 14-37 फीसदी की सीमा को घटाकर 5-25 फीसदी करने की बात कही गई है। अप्रत्यक्ष भुगतान पर सख्ती और अधिक पारदर्शिता के प्रावधान भी बैंकों की कमाई के मौजूदा माडल को प्रभावित कर सकते हैं। बदलेगी बीमा वितरण रणनीति: इन बदलावों के जवाब में बैंक अपनी बीमा रणनीति में बदलाव कर सकते हैं। वे बेहतर कमीशन वाले दीर्घकालिक बीमा उत्पादों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और कम कमीशन वाले उत्पादों की भरपाई अधिक बिक्री के जरिये करने की कोशिश कर सकते हैं। जिन बैंकों की बीमा कंपनियों में हिस्सेदारी है, वे अपने समूह की कंपनियों के उत्पादों को प्राथमिकता दे सकते हैं। केयरएज का अनुमान है कि बहु-साझेदार बैंकों में पहले साल का भुगतान करीब 40 फीसदी तक घट सकता है, जिससे वे लागत कम करने, बिक्री बढ़ाने या उत्पादों की अवधि बदलने जैसे विकल्प अपना सकते हैं। सामान्य बीमा में बैंक द्वारा जुटाए गए प्रीमियम की हिस्सेदारी करीब 5 फीसदी है, लेकिन इससे लगभग 26% कमीशन मिलता है, इसलिए इस क्षेत्र पर खास असर पड़ सकता है। बड़े बैंकों पर सीमित, छोटे बैंकों पर अधिक प्रभाव: आईआईएफएल कैपिटल के अनुसार, बड़े बैंकों के कुल मुनाफे पर इसका असर सीमित रहने का अनुमान है, क्योंकि बैंकएश्योरेंस आय कुल शुल्क आय का लगभग 10 फीसदी और कर बाद मुनाफे का करीब 3 फीसदी है।

बिजनेस: अमेजन, फ्लिपकार्ट पर 10-10 लाख व जियोमार्ट पर पांच लाख का जुर्माना, सीसीपीए ने की कार्रवाई

नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने अमेजन व फ्लिपकार्ट पर 10-10 लाख रुपये व जियोमार्ट पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। तीनों ई-कामर्स प्लेटफार्म पर साइक्लोसिनोन हर्बिसाइड नामक बिना पंजीयन वाले कृषि-रसायन उत्पाद को बेचने और उसका विज्ञापन करने का आरोप है। 22 सितंबर के एक अलग आदेश में उपभोक्ता संरक्षण नियामक ने तीनों ई-कामर्स कंपनियों को उस उत्पाद की बिक्री और विज्ञापन तुरंत रोकने का निर्देश दिया है जिसे उसके एक्टिव इंग्रीडिएंट के रसायन नाम या उसके कंपोजिशन का खुलासा किए बिना बेचा जा रहा था। सीसीपीए ने इन प्लेटफार्म्स को ऐसे उत्पाद की लिस्टिंग रोकने के लिए सेल्फ-आडिट करने का भी निर्देश दिया जो मौजूदा कानूनों का उल्लंघन करते हैं या उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। नियामक ने तीन प्लेटफार्म से 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने को कहा है। दरअसल, सीसीपीए को केंद्रीय कृषि मंत्रालय से मिली एक शिकायत के बाद यह जांच शुरू हुई। इसे मूल रूप से क्राप केयर फेडरेशन आफ इंडिया (सीसीएफआई) ने दर्ज कराया था। जांच के दौरान कृषि मंत्रालय ने सीसीपीए को बताया कि साइक्लोसिनोन नाम का कोई भी रसायन कीटनाशक अधिनियम-1968 की अनुसूची में शामिल नहीं है।

भारत नई निवेश संधियों के साथ एफडीआई आकर्षित करने को तैयार

नई दिल्ली

संशोधित ढांचे पर आधारित चार द्विपक्षीय निवेश संधियां (बीआईटी) अंतिम चरण में

भारत अपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आवक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चार महत्वपूर्ण द्विपक्षीय निवेश संधियों (बीआईटी) को अंतिम रूप देने के बेहद करीब है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि ये संधियां एक संशोधित ढांचे पर आधारित होंगी, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल से जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस पहल का लक्ष्य एफडीआई में हालिया गिरावट को रोकना है, जहां पिछले चार वर्षों में शुद्ध एफडीआई वित्त वर्ष 2020-22 के लगभग 40 अरब डालर के औसत से घटकर अब 6.95 अरब डालर रह गया है।

भारत वर्तमान में ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ओमान और कतर के साथ बीआईटी के लिए बातचीत के अंतिम चरण में है, जबकि कनाडा के साथ हाल ही में चर्चा शुरू हुई है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी पुष्टि की है कि भारत और आस्ट्रेलिया भी एक बीआईटी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026 के अपने बजट भाषण में भारत के बीआईटी ढांचे की समीक्षा की घोषणा करते हुए इसे निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल बनाने और पहले भारत का विकास की भावना को बढ़ावा देने पर जोर दिया था। भारत का मौजूदा बीआईटी ढांचा वर्ष 2015 में लागू हुआ था, जिसके बाद सरकार ने 2016 में 50 से अधिक साझेदारों के साथ अपनी संधियों को रद्द कर दिया था।

अधिकांश साझेदारों ने 2016 के ढांचे को प्रतिबंधात्मक बताया था, खासकर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता शुरू करने से पहले पांच साल तक स्थानीय कानूनी उपायों के इस्तेमाल की शर्त के कारण। यही वजह थी कि निवेश की नई संधियों को अंतिम रूप देना मुश्किल हो गया था। हालांकि, वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने संकेत दिया है कि अद्यतन बीआईटी ढांचे में भी स्थानीय कानूनी उपाय वाला यह प्रावधान बरकरार रहने की संभावना है। इस बीच, आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) की सचिव अनुराधा ठाकुर ने भी पिछले महीने कहा था कि सरकार बीआईटी ढांचे में बदलाव के तहत विवाद सुलझाने सहित कई अन्य प्रावधानों पर विचार कर रही है, जो विदेशी निवेश आकर्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।

भारत पर महंगा पड़ेगा रूसी तेल का विकल्प

नई दिल्ली । रूस से कच्चे तेल के आयात में कमी करने पर भारत को सालाना अरबों डालर का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह कदम न केवल वित्तीय बोझ बढ़ाएगा बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के लिए भी बड़ी चुनौती बन सकता है। एक रिपोर्ट बताती है कि यदि भारत प्रतिदिन लगभग 10 लाख बैरल रूसी कच्चे तेल की जगह महंगे विकल्प अपनाता है, तो उसे हर साल 1.8 से 3.7 अरब डालर अधिक खर्च करने पड़ सकते हैं। इन वैकल्पिक स्रोतों से मिलने वाला तेल रूसी तेल के मुकाबले करीब 5 से 10 डालर प्रति बैरल महंगा हो सकता है। यदि यह विकल्प 20 लाख बैरल प्रतिदिन तक बढ़ता है, तो यह अतिरिक्त खर्च दोगुना हो सकता है, जैसा कि कमोडिटी एक्सपर्ट नताल्या काटोना का अनुमान है। हालांकि, वित्तीय बोझ से भी बड़ी चुनौती इतनी बड़ी मात्रा में कच्चे तेल की वैकल्पिक आपूर्ति खोजना है। अगस्त में रूस ने भारत को लगभग 19 लाख बैरल प्रतिदिन तेल भेजा, जो देश के कुल कच्चे तेल आयात का करीब 42 फीसदी था। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के एक अधिकारी के मुताबिक जुलाई में रूस की हिस्सेदारी 52 फीसदी तक पहुंच गई थी, जिसे किसी अन्य स्रोत से बदलना बेहद कठिन होगा। भारत सरकार अपनी ऊर्जा जरूरतों और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देती रही है। अक्टूबर से मार्च-अप्रैल तक ईंधन की सर्वाधिक मांग और रिफाइनरियों की पूर्ण क्षमता को देखते हुए कुल आयात घटाना भी संभव नहीं होगा।

एआई विकास में राष्ट्रों के अधिकार का समर्थन: जयशंकर

संयुक्त राष्ट्र में बोले विदेश मंत्री, भारत ग्लोबल साउथ के साथ एआई को जनहित में विकसित करेगा

नई दिल्ली

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के हालिया सत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विकास में हर देश के संप्रभु अधिकार का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी देश अपने लक्ष्यों और जरूरतों के हिसाब से अपना एआई माडल तैयार कर सकता है और उसका इस्तेमाल कर सकता है।

जयशंकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत ग्लोबल साउथ के देशों के साथ मिलकर एआई को जनहित और आर्थिक विकास के लिए आगे बढ़ाना चाहता है। जयशंकर ने एआई को केवल एक नई तकनीक के बजाय लोगों के जीवन को आसान बनाने, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और व्यापक समस्याओं को हल करने का एक शक्तिशाली उपकरण बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने इसी साल फरवरी में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी की थी, जिसमें वैश्विक विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया था। विदेश मंत्री ने दोहराया कि हर देश की जरूरतें और प्राथमिकताएं अलग होती हैं, इसलिए उन्हें अपने एआई माडल बनाने और उनके उपयोग का तरीका तय करने का अधिकार होना चाहिए। भारत अपनी ग्लोबल साउथ साझेदारी में ढ्ढ को महत्वपूर्ण स्थान देगा। विदेश मंत्री ने ग्लोबल साउथ के देशों के सामने आने वाली गंभीर चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला, जिनमें भोजन, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़ी चार प्रमुख समस्याएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सुपर अल नीनो, उर्वरकों की कमी और अनाज के परिवहन में बाधाओं से इन देशों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, जिसका असर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिशों पर भी पड़ रहा है। जयशंकर ने बाजार पहुंच में रुकावटों और गैर-बाजार गतिविधियों के कारण औद्योगिक विकास में आ रही बाधाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने तकनीक के प्रसार के साथ ही विचारों और हितों के आपसी सम्मान, सहयोग और सांस्कृतिक समझ पर भी जोर दिया, ताकि वैश्विक शांति और समृद्धि को बढ़ावा मिल सके।

महंगी हुई मारुति सुजुकी की सेलेरियो और आल्टो के10

नई दिल्ली

अपने ग्राहकों को झटका देते हुए मारुति सुजुकी ने अपनी किफायती हैचबैक सेलेरियो और आल्टो के10 की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। हालांकि, इसके बेस एलएक्सआई वेरिएंट और सीएनजी माडल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे इन खरीदारों को राहत मिली है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, सेलेरियो के वीएक्सआई, झेडएक्सआई और झेडएक्सआई प्लस पेट्रोल वेरिएंट अब 2,500 रुपये महंगे हो गए हैं। मारुति सेलेरियो में 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर के 10 सी पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 66 बीएचपी की पावर और 89 एनएम का टार्क पैदा करता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबाक्स विकल्पों के साथ खरीदा जा सकता है, जिसमें पेट्रोल एएमटी वेरिएंट 26 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है। वहीं, सीएनजी माडल में यही इंजन 56 बीएचपी की पावर और 82 एनएम का टार्क देता है, जिसका दावा किया गया माइलेज 34.43 किलोमीटर प्रति किलोग्राम है और यह केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबाक्स के साथ आता है। सुरक्षा के लिहाज से, ग्लोबल एनकैप की हालिया टेस्टिंग में 6 एयरबैग वाले सेलेरियो वेरिएंट को 3-स्टार एडल्ट आक्यूपेंट प्रोटेक्शन रेटिंग मिली थी। सेलेरियो के अलावा, मारुति सुजुकी ने अपनी आल्टो के10 की कीमतों में भी 2,500 रुपये की बढ़ोतरी की है।

इस बढ़ोतरी में वीएक्सआई (ओ) पेट्रोल मैनुअल, एलएक्सआई (ओ) सीएनजी, वीएक्सआई (ओ) पेट्रोल आटोमैटिक और वीएक्सआई (ओ) सीएनजी जैसे चुनिंदा वेरिएंट शामिल हैं। आल्टो के10 में के-सीरीज 1.0-लीटर ड्यूल जेट, ड्यूल वीवीटी इंजन दिया गया है। इसका आटोमैटिक वेरिएंट 24.90 केएमपीएल और मैनुअल वेरिएंट 24.39 केएमपीएल का माइलेज देता है, जबकि सीएनजी वेरिएंट का माइलेज 33.85 किमी/किग्रा है। कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बड़े अपडेट करने की तैयारी में है, जिसके तहत जल्द ही 7-सीटर ग्रैंड विटारा और अर्टिगा फेसलिफ्ट की एंट्री होगी। 7-सीटर ग्रैंड विटारा का कोडनेम वाय 17 है और इसे 2027 में लान्च किए जाने की उम्मीद है, जिसमें 6 और 7 सीटों का विकल्प मिल सकता है।

बेंटले ने लान्च किए पावरफुल टार्कल एस के साथ दो वेरिएंट

नई दिल्ली। लग्जरी कार निर्माता बेंटले कंपनी की पहली बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (बीईवी) को स्टैंडर्ड टार्कल और अधिक पावरफुल टार्कल एस के साथ दो वेरिएंट में पेश किया है। कंपनी के इन दोनों ही माडल में 113.2 किलोवाट आवर की दमदार बैटरी दी गई है। डब्ल्यूएलटीपी के अनुसार, इसकी अधिकतम क्लेम्ड रेंज 600 किलोमीटर तक है। चार्जिंग के मामले में, 400 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर से बैटरी को मात्र 16 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है। यह एसयूवी सिर्फ 2.9 सेकंड में 0-100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है, जो इसे बेहद तेज बनाती है। टार्कल के साथ बेंटले ने अपनी नई डिजाइन भाषा की शुरुआत की है, जिसमें लंबा व्हीलबेस, छोटे ओवरहैंग और एक नया फ्रंट डिजाइन मिलता है। इसमें डायमंड पैटर्न वाली इल्यूमिनेटेड ग्रिल दी गई है, जिसमें 76 एलईडी डायमंड एलिमेंट का उपयोग किया गया है। यह बेंटले के नए डिजाइन वाले लोगो के साथ आने वाली पहली कार भी है। इंटीरियर में बेंटले की पारंपरिक विंग-इंस्पायर्ड डैशबोर्ड डिजाइन को आधुनिक डिजिटल इंटरफेस के साथ जोड़ा गया है। लेदर, वूल, वुड और एल्यूमीनियम जैसी प्रीमियम फिनिश के साथ इसमें 16-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड हैं। आडियो के लिए इसमें 16-स्पीकर, 620 वाट सिस्टम या वैकल्पिक रूप से 28-स्पीकर वाला नेम फार बेंटले सिस्टम मिलता है, जो डाल्बी ऐटमास को सपोर्ट करता है। पावर की बात करें तो, टार्कल में दो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर दी गई हैं। बेंटले ने इसमें पेट्रोल इंजन की आवाज की नकल करने के बजाय बेंटले डायनामिक सिम्फनी नामक खास साउंड सिस्टम दिया है।